रोगों की रोकथाम और उन्हें फैलने से रोकने के लिए लगभग 20 लाख टीके और 179308 रु० की दवाइयां और शल्य चिकित्सा उपकरण भेजे हैं ।

(ii) राज्य सरकार ने पुरुलिया, बंकुरा, पश्चिम दिनाजपुर, बर्दवान, मिदनापुर, मालदा, बीरभूम, नादिया, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली और 24 परगना जिलों में सूखा राहत कार्यों के लिए 13 लाख रुपए की राशि नियत की थी ।

Villages affected by Severe Scarcity

1839. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) how many villages in each district of each State have been affected by severe scarcity and declared "Scarcity-hit";

(b) nature of such scarcity; and

(c) State-wise number of people affected?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) and (c). Information is being collected.

(b) Drought conditions have developed due to inadequate and erratic rainfall.

राज्यों में सूखा के कारण खरीफ की फसल को क्षति और उसके लिए केन्द्रीय सहायता

1840. **श्री धनशाह प्रधान :**

श्री अजीत कुमार साहा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार सूखे की स्थिति के कारण खरीफ की फसल की हुई क्षति के बारे में जानकारी एकत्र कर ली है ; और यदि हां, दो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की और उन्हें कितनी राशि दी गई तथा इस बारे में क्या अन्य उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चालू वर्ष में कम और अनियमित वर्षा होने के कारण कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में खरीफ की फसलों पर बुरा असर पड़ा था और खरीफ के उत्पादन में काफी कमी होने की आशंका थी । तथापि अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर में महीनों में व्यापक वर्षा के परिणामस्वरूप खरीफ की फसलों में सुधार हुआ । इसके परिणामस्वरूप पहले खरीफ उत्पादन में जितनी कमी होने की संभावना थी, आशा है उससे काफी कमी होगी तथापि 1972–73 के दौरान खरीफ उत्पादन के पक्के अनुमान अभी राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) खरीफ उत्पादन में हुई कमी को पूरा करने और रबी तथा ग्रीष्मकालीन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने चालू कृषि वर्ष में आयात कृषि उत्पादन कार्यक्रम शुरु किया है । इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को शीघ्र पूरा करके 31 मार्च, 1973 तक चालू किए जा सकने वाले लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए 152.40 करोड़ रुपए का ऋण सहायता के रूप में दिया गया है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को बीज, उर्वरकों और कीटनाशियों आदि आदानों की खरीद के लिए 92 करोड़ रुपये का एक अल्पकालीन ऋण भी दिया गया है । एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा है जिसमें केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या LT–4381/73**]